

Regarding need to set up a monitoring system to oversee the utilization of funds allocated under MGNREGS in Odisha-Laid

श्री प्रदीप पुरोहित (बारगढ़) : ओडिशा की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मनरेगा योजना के तहत आवंटित धन को निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे अन्य मदों में अनुचित रूप से स्थानांतरित कर दिया गया। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि श्रमिकों की जगह मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। इस अनियमितता के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिला, जिससे उन्हें अन्य राज्यों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे न केवल ओडिशा की ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि हजारों गरीब श्रमिकों के जीवन-यापन पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस पूरे मामले की गहन जाँच हेतु एक उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित की जाए और मनरेगा फंड के उचित उपयोग की निगरानी के लिए एक स्थायी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियों को रोका जा सके और जरूरतमंद श्रमिकों को उनके अधिकारों के अनुरूप रोजगार मिल सके।